खंड १८ नंबर ३ जुलाई २०२२

आरआईएस डायरी

–अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, भारत श्रीमती मीनाक्षी लेखी एसएईएस, 2022 में उद्घाटन भाषण दे रही हैं।

तेरहवां दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस)

दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) एक प्रमुख ट्रैक 1.5 एक्सरसाइज तथा इस क्षेत्र के शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, राजनयिकों और अन्य विशेषज्ञों का अपनी किस्म का एक नीतिगत मंच है, जिसे दक्षिण एशियाई देशों के बीच बारी–बारी से वार्षिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाता है। तेरहवां एसएईएस नई दिल्ली में 19 और 20 अप्रैल, 2022 को आरआईएस और सहयोगी संस्थाओं द्वारा आयोजित किया गया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में रोज़ग. ार के अवसरों में वृद्धि, एफडीआई, ज्ञान भागीदारी को बढ़ावा देने, व्यापक डिजिटलीकरण प्राप्त करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण में तेजी लाने में व्यापार और कनेक्टिविटी की भूमिका पर बल दिया। आरआईएस के अध्यक्ष, राजदूत डॉ मोहन कुमार ने दक्षिण एशिया में लचीली मूल्य श्रृंखलाओं का लाभ उठाने और एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति पर अपनी चिंता को रेखांकित किया। आईपीएस, श्रीलंका की कार्यकारी निदेशक दुश्नी वीरा. कून ने 12वें एसएईएस की रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा दो मुख्य मुद्दों खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा डेटा निजता और जवाबदेही को रेखांकित किया।

माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने अपने उद्घाटन भाषण में मौजूदा दौर में कई चुनौतियों का सामना कर रहे इस क्षेत्र में त्वरित और गहन तालमेल प्राप्त करने के लिए 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति को 'नेबरहुड फास्ट' की नीति में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्रीमती लेखी ने क्षेत्र को डेटा जेनरेटर और निर्माता के रूप में उल्लेखित करते हुए दक्षिण एशियाई देशों से 'डेटा नियंत्रक' विशाल प्रौद्योगिकी कंपनियों (यानी बिग टेक) के 'डेटा साम्राज्यवाद' से सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय स्तर पर मानक–निर्धारण में सहयोग करने का आग्रह किया। कम कने. क्टिविटी और अपर्याप्त अंतर क्षेत्रीय व्यापार को रेखांकित करते हुए श्रीमती लेखी ने सभी आयामों में एकीकरण को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय मल्टी–मॉडल को वास्तविक के साथ ही साथ डिजिटल और वित्तीय कनेक्टिविटी की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

श्रीमती लेखी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि दक्षिण एशिया में सहयोग पांच 'सी' : कलेक्टिव कोऑपरेशन (यानी सामू. हिक सहयोग), कैपेसिटी बिल्डिंग (यानी क्षमता निर्माण), कनेक्टिविटी (यानी संपर्क), कल्चरल कनेक्ट (यानी सांस्कृतिक संपर्क) और कम्युनिटी कनेक्ट (यानी सामुदायिक संपर्क) पर आधारित होना चाहिए। प्रथम पूर्ण सत्र, 'महामारी के पश्चात विकास की आवश्यकताएं: क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दे' के दौरान सार्वजनिक और निजी निवेश, सामाजिक सुरक्षा तंत्र, असमानता को दूर करने के लिए वितरण नीतियों, बाहरी स्रोतों से उधार, ऊर्जा सहयोग और पोस्ट–कोविड रिकवरी में क्रॉस–बॉर्डर कनेक्टिविटी को सदृढ़ बनाने के महत्व पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, महामारी के बाद की चुनौतियों से निपटने और क्षेत्रीय

...शेष पृष्ठ 2 पर जारी

तेरहवां दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस)

...शेष पृष्ठ 1 से जारी

व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और व्यापक सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। दक्षिण एशियाई देशों में संस्थागत सहायता और क्षेत्रीय पहल इस क्षेत्र को सुधार, व्यापक एकीकरण और विकास के मार्ग पर अग्रसर करेगी।

डॉ. दुश्नी वीराकून

आरआईएस–यूएनइ. 'एससीएपी सत्र 'व्यापार सहयोग और मूल्य श्रृंखला स्थानीयकरण' पर था। अंतर–क्षेत्रीय व्यापार की परिपाटियों, क्षेत्रीय आर्थिक विकास की गतिशीलता और क्षेत्रीय पहचान के आर्थिक आधार पर प्रस्तुति दी गई। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद, एक–दूसरे पर स्थानीय निर्भरता है, जिसके परिणामस्वरूप तीन स्तंभों : व्यापार निवेश, कनेक्टिविटी और शुल्क बाधाओं पर आधारित मूल्य श्रृंखला के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार हुआ। सामान्य वस्तुएं बनाने और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के तौर–तरीके और साधन तलाशने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। एक अन्य मुद्दा यह उठाया गया कि व्यापार को आर्थिक विकास का वाहक स्वीकार करने के बावजूद, दक्षिण एशिया के आसपास के देशों ने अंतर–क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया कि दक्षिणीय व्यापार प्रवाह में दक्षिणीय सहयोग में वृद्धि के कारण मूल्य श्रृंखलाएं अधिक वैश्विक हो गई हैं। सत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

डॉ. फहमिदा खातून

तृतीय पूर्ण सत्र क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के भविष्य पर केंद्रित था। इसने दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी में व्यापार सुविधा उपायों के महत्व पर जोर दिया। इसमें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में बंदरगाह की बुनियादी सुविधाओं और अंतर्देशीय जलमार्गों की भूमिका के बारे में भी चर्चा की गई। इसके अलावा, आर्थिक गलियारा कनेक्टिविटी, ढांचागत परियोजनाओं के लिए निरंतर वित्त पोषण, बाधित व्यावसायिक और कामगार गतिशीलता, राजनीति, संस्थाओं और भूगोल में खुलापन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ऐसी प्रक्रियाओं को भी लागू करने की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक, जवाबदेह, कानून के शासन के अनुसार, पारदर्शी हों और नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों की भागीदारी की अनुमति देती हों।

प्रोफेसर बिश्वंभर पयाकुर्याल

आरबीआई के अंतर्राष्ट्रीय विभाग में निदेशक श्रीमती स्मिता शर्मा ने मध्याह्न भोजन के दौरान विशेष व्याख्यान में सार्क वित्त की भूमिका को दक्षिण एशियाई केंद्रीय बैंकों के लिए मौद्रिक नीति, भुगतान प्रणाली, क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के मंच के रूप में वर्णित किया। उसी सत्र में क्रिप्टो करंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसीज़(सीबीडीसी) सहित कुछ अन्य मुद्दों को भी रेखांकित किया गया।

प्रोफेसर मुस्तफिजुर रहमान

'खाद्य प्रणालियों और मूल्य प्राप्ति के लिए संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र' विषय पर प्रथम समानांतर सत्र में कृषि मशीनीकरण के लिए कम लागत वाली टिकाऊ प्रौद्योगिकियां, डिजिटल परिदृश्य का महत्व, कृषि उत्पादन के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण, निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाली कृषि, अग्रसक्रिय नवीन सब्सिडी प्रबंधन और स्मार्ट कृषि जैसे कई हस्तक्षेपों का आह्वान किया गया। सत्र में उत्पादन नेटवर्क्स की क्षमता और तकनीकी दक्षता को बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया गया। पौष्टिक भोजन तक पहुंच से संबंधित मुद्दों और इससे संबंधित हस्तक्षेपों पर भी चर्चा की गई।

द्वितीय समानांतर सत्र 'सभी के लिए स्वास्थ्य और डिजिटल स्वास्थ्य पहल' विषय पर आधारित था। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने की दिशा में दक्षिण एशियाई देशों द्वारा की गई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। सत्र में जन भागीदारी वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, डिजिटल रूप से सक्षम विकेन्द्रीकृत और डेटा–संचालित निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो जहां तक संभव हो सके घर में या घर के आसपास सभी आयामों में देखभाल को सक्षम बनाती है। मजबूत सीएसओ और स्वास्थ्य के लिए समुदाय आधारित सक्रियता भी महत्वपूर्ण है। "सभी के लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य हासिल करने में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

तृतीय समानांतर 'ऊर्जा कनेक्टिविटी से लाभ उठाना' विषय पर था, जिसमें दक्षिण एशिया में बिजली के क्रॉस–बार्डर प्रवाह को सुगम बनाने के लिए नियमों के सामंजस्य पर जोर दिया गया जो पर्यावरण के अनुकूल संक्रमण की दिशा में सर्वोपरि है। इस क्षेत्र को बिजली और टिकाऊ ऊर्जा की आवश्यकता है। सतत संक्रमण के संदर्भ में, ऊर्जा संक्रमण चुनौतीपूर्ण होने के साथ–साथ महंगा भी है। यदि दक्षिण एशिया को स्थायी संक्रमण की दिशा में अग्रसर होना है, तो उचित प्राथमिकता के आधार पर नीति निर्धारण किए जाने की आवश्यकता होगी। इस बात का उल्लेख बहुत स्पष्ट रूप से किया गया कि ताजे जल और ऊर्जा के पर्याप्त स्रोत होने के बावजूद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा कनेक्टिविटी के संदर्भ में संबद्धता कम है, यह जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भर है।

समापन सत्र में सतत जीवन शैली के माध्यम से निरंतर संक्रमण को सक्षम करने के दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सीओपी26 शिखर सम्मेलन, ग्लासगो में अपने संबोधन के दौरान व्यक्त ' आइडियाज़ ऑफ लाइफः लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट' की

...शेष पृष्ठ 3 पर जारी

गाम्बिया के शिष्टमंडल के साथ प्रोफेसर एस. के. मोहंती

गाम्बिया से शिष्टमंडल

गाम्बिया के वरिष्ठ सिविल सेवकों के एक शिष्टमंडल ने 20 मई, 2022 को आरआईएस का दौरा किया। प्रोफेसर एस. के. मोहंती ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें आरआईएस की कार्य प्रणाली की जानकारी दी। भारत में गाम्बिया गणराज्य के उच्चायुक्त महामहिम श्री मुस्तफा जवारा ने प्रारंभिक भाषण दिया।

इसके बाद आरआईएस के मुख्य वक्ताओं प्रोफेसर एस. के. मोहंती, डॉ पी.के. आनंद और डॉ प्रियदर्शी दाश ने संबोधित किया। यह शिष्टमंडल राष्ट्रीय सुशासन, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत केंद्र, भारत सरकार द्वारा आयोजित किए गए गाम्बिया के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए एक सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत आया था। आरआईएस के प्रकाशन *75 ईयर्स ऑफ डेवलॅपमेंट पार्टनरशिप : सागा ऑफ कमिटमेंट टू प्लूरे. लिटी, डाइवर्सिटी एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस'* की प्रतियां प्रतिनिधियों के साथ साझा की गईं। ■

को–विन टीकाकरण मंच पर जीडीसी भारत–युगांडा द्विपक्षीय सत्र

आरआईएस के ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर (जीडीसी) ने 4–5 मार्च, 2020 को दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय मंडप का दौरा करने तथा 'को–विन टीकाकरण प्लेटफॉम' और 'एनआईपीएल द्वारा डिजिटल भुगतान की पेशकश' पर आयोजित कार्यशालाओं में भाग लेने वाले बड़ी संख्या में अफ्रीका के वार्ताकारों के साथ अपनी प्रारंभिक बातचीत के आधार पर आगे बढ़ने का क्रम जारी रखा।

उसी संदर्भ में जीडीसी द्वारा युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओएच) के साथ फॉलोअप किया गया, ताकि उनकी विशिष्ट दिलचस्पी का पता लगाया जा सके और आगे के कदम निर्धारित किए जा सकें। इसके उत्तर में, एमओएच–युगांडा ने कोविन के पंजीकरण मॉड्यूल में अपनी दिलचस्पी की जानकारी दी और कोविन के संबंध में एक तकनीकी प्रस्तुति और डेमो दिए जाने का अनुरोध किया। इसके बाद, जीडीसी ने 28 जून, 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए), भारत सरकार और एमओएच, युगांडा के बीच एक तकनीकी सत्र और डेमो की व्यवस्था की। एमओएच, युगांडा के शिष्टमंडल का नेतृत्व स्वास्थ्य सूचना प्रभाग में सहायक आयुक्त श्री मबाका पॉल ने किया।

एनएचए की ओर से प्रस्तुति सीईओ के विशेष कार्य अधिकारी श्री अविरल गुप्ता ने दी। उन्होंने समावेशिता और इंटरऑपरेबिलिटी, विविध हितधारकों के लिए मामलों का उपयोग, रीयलटाइम डैशबोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता आदि सहित कोविन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। एनएचए की प्रस्तुति और डेमो के बाद इंटरेक्टिव सेशन हुआ। एमओएच, युगांडा की तकनीकी टीम ने समग्र प्रस्तुति की बहुत सराहना की और यह युगांडा में डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एनएचए के साथ समझौता ज्ञापन करने की दिशा में गति प्रदान कर सकती है। ■

तेरहवां दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस)

...शेष पृष्ठ 2 से जारी

अवधारणा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। क्षेत्र में पर्वतों और समुद्री संसाधनों के महत्व के मद्देनजर सत्र के दौरान नीली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निरंतरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। समापन सत्र में इस बात को भी रेखांकित किया गया कि यह क्षेत्र विकास के इंजन के रूप में व्यापार के साथ उन्नति कर रहा है। संस्थाओं, व्यक्तियों, नागरिक संगठनों को सार्क की भावना को एक संगठन के रूप में और दक्षिण एशिया के विचार को एक क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता है। एसएईएस के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में संयुक्त सचिव (पीपी एंड आर), डॉ सुमित सेठ ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

(समापन सत्र के अधिक परिप्रेक्ष्यों को जानने के लिए कृपया पिछला पृष्ठ देखें। एसएईएस, 2022 की पूरी रिपोर्ट आरआईएस वेबसाइट www.ris.org.in पर उपलब्ध है) ■

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए क्षितिज: जी–7 और जी–20 के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना

हाल के वर्षों में भू–राजनीतिक परिदृश्य, विशेषकर व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सार्वजनिक समान और विकास वित्त जैसे आर्थिक मुद्दों में बड़े पैमाने पर बदलाव आए हैं। जी–20 और जी–7 जैसे बहुपक्षीय मंच उन मुद्दों को व्यापक रूप से कवर कर रहे हैं तथा क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के नए स्वरूपों को तलाशने में मदद कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सामान्य मुद्दों ने दोनों मंचों पर समान रूप से ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए वे जी–7 और जी–20 के बीच समन्वित सहयोग का कारण बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों मंचों द्वारा विचारों और दृष्टिकोणों को संभावित रूप से साझा किए जाने को लेकर स्पष्ट आशंकाएं हैं।

इस बदलते परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर, आरआईएस ने जर्मनी के दूतावास के सहयोग से नई दिल्ली में 7 जून, 2022 को देशों के बीच सहयोग के नवीन विचारों और प्रारूपों पर विचार–विमर्श करने के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए क्षितिजः जी–7 और जी–20 के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना' विषय पर एक हाइब्रिड कार्यक्रम का आयोजन किया। जर्मनी सरकार में राज्य सचिव श्री जोचेन फ्लैसबर्थ और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव (आर्थिक संबंध) श्री दम्मू रवि ने दोनों सरकारों के विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों और पहलों को साझा किया, जो संभवतः जी–7 और जी–20 के बीच आदान–प्रदान को सुगम बना सकते हैं।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने संदर्भ निर्धारित करते हुए चर्चा की शुरुआत की। इस पैनल चर्चा में योगदान देने वाले विशेषज्ञों में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (यूरोप पश्चिम) श्री संदीप चक्रवर्ती; नई दिल्ली में जर्मनी के दूतावास में प्रभारी राजदूत डॉ स्टीफ़न ग्रैबर; कार्नेगी इंडिया, नई दिल्ली में निदेशक डॉ रुद्र चौधरी ;जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, बॉन में हैड ऑफ प्रोग्राम डॉ स्टीफ़न क्लिंगबील; प्रोफेसर, यूरोपीय अध्ययन केंद्र, जेएनयू, नई दिल्ली

संगोष्ठी में उपस्थित विशिष्ट अतिथि

के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा; और जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज, हैम्बर्ग की अध्यक्ष प्रोफेसर अमृता नार्लीकर शामिल थे।

इस संगोष्ठी में जी–7 जी–20 के दृष्टिकोण और दोनों मंचों की गतिविधियों के बीच संभावित सहयोग के माध्यम से वैश्विक शासन प्रणाली के मुद्दों पर विचार किया गया। जिन मुद्दों ने संयुक्त कार्रवाई के लिए प्रेरित किया उनमें एजेंडा 2030 और कोविड के बाद के वर्षों में व्यवस्थित रिकवरी सुनिश्चित करना शामिल है। कोविड महामारी जैसे वैश्विक संकट की स्थिति में प्रभावी अंतरराष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित है। ऐसी साझेदारियां विश्वास और सहयोग की भावनाओं में गूंथी जानी चाहिए। भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी अनेक अवसरों का वादा करती है और इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। विविधताओं के बावजूद जी–7 और जी–20 संपर्क को भारत–जर्मन साझेदारी से मजबूत किया जा सकता है। बर्लिन में भारत–जर्मन सरक. ार के परामर्श तथा पर्यावरण के अनुकूल और सतत विकास के लिए भारत–जर्मन साझेदारी पर हस्ताक्षरों ने इस सहयोग को शिखर तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा, टीके, डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां यह साझेदारी सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा दे सकती है। भारत और जर्मनी को एसडीजी हासिल करने की दिशा में सुसंगत रूप से आगे बढ़ना चाहिए और वैश्विक संरचना में कुछ बड़े पैमाने पर पुनर्गठन करना चाहिए। एक अन्य प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा संक्रमण है, जहां इस तरह की द्विपक्षीय साझेदारियां बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। बदलते वैश्विक समाधानों को देखते हुए भारत और जर्मनी के पास भी अब आर्थिक और रक्षा सहयोग विकसित करने के लिए व्यापक प्रोत्साहन हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर गौर करना उचित होगा कि ऐसे मुद्दों को जी–7 फोरम में उपयुक्त रूप से हल किया जा सकता है। इस प्रकार, 2023 में भारत की जी–20 अध्यक्षता और जर्मनी की जी–7 अध्यक्षता के दौरान जी–7, भारत और जर्मनी दोनों द्वारा वर्तमान वैश्विक प्राथमिकताओं को दर्शाने वाले शक्तिशाली सिग्नलिंग तंत्र की भूमिका निभा सकता है। ■

वेबिनार में प्रमुख वक्ता

बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और बाह्य अंतरिक्ष अधिकार में उभरती चुनौतियां

आरआईएस के फोरम फॉर इंडियन साइंस डिप्लोमेसी (एफआईएसडी) ने 27 मई 2022 को प्रोफेसर एस.के. मोहंती और डॉ. बी. बालकृष्णन, साइंस डिप्लोमेसी फेलो की अध्यक्षता में 'बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और बाह्य अंतरिक्ष अधिकार में उभरती चुनौतियां' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

अपने उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर मोहंती ने अंतरिक्ष से संबंधित भारत के कार्यकलापों के सामाजिक अनुप्रयोगों – डिजिटल भेद को मिटाने, कृषि और वानिकी मानचित्रण, जलवायु परिवर्तन की निगरानी और शमन पर जोर दिया–तथा श्रोताओं के समक्ष अंतरिक्ष उद्योग के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों का संक्षिप्त विव. रण प्रस्तुत किया। उन्होंने अंतरिक्ष से संबंधित इन कार्यकलापों को भारत के एसडीजी और भारत के घरेलू सामाजिक–आर्थिक विकास से जोड़ा। चुनौतियों के मोर्चे पर प्रोफेसर मोहंती ने 'अंतरिक्ष मलबे' को रेखांकित करते हुए कहा कि यह एक कानूनी मुद्दा है। अंतरिक्ष कूटनीति के मोर्चे पर, उन्होंने कहा कि भारत को अपने प्रौद्योगिकी विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रदान करना जारी रखना चाहिए।

वेबिनार की शुरुआत "पृथ्वी की कक्षाओं के अधिकार में उभरती चुनौतियां" सत्र के साथ हुई। इस सत्र में भारतीय अंतरिक्ष आयोग के सदस्य डॉ. ए.एस. किरण कुमार, इसरो मुख्यालय में सिस्टम्स प्लानिंग एंड एनालिसिज ग्रुप के पूर्व सदस्य प्रोफेसर वी. सिद्धार्थ, और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में विशिष्ट फेलो लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू ने भाग लिया।

डॉ. ए.एस. किरण कुमार ने वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में उभरते रुझानों और बढ़ती अंतरिक्ष पहुंच का हवाला देते हुए सत्र में विचार–विमर्श का रुख निर्धारित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अंतरिक्ष गतिविधियां अब अंतरिक्ष एजेंसियों का ही कार्यक्षेत्र नहीं रह गई हैं, बल्कि निजी क्षेत्र भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। उन्होंने शिक्षा और उद्योग जगत के साथ इसरो की बातचीत, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कई अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के निजीकरण और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्व का उल्लेख किया।

अगले वक्ता प्रोफेसर वी. सिद्धार्थ ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि चंद्रमा अब पृथ्वी की कक्षाओं से दूर नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की कक्षा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे एक विवादित क्षेत्र है तथा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विस्तार का कोई भी प्रयास कठिनाइयों भरा है।

इस सत्र के अंतिम वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू थे। उन्होंने हाई–रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग तथा संचार, कमान, नियंत्रण, कंप्यूटर, सूचना, निगरानी और सर्वेक्षण (सी4 आइ. ंएसआर) के महत्व पर बल दिया।

दूसरे सत्र का शीर्षक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के अवसरों का चुनौतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना था। इसमें सेंटर फॉर कंटेम्पररी चाइना स्टडीज के लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन, सैटकॉम इंडस्ट्री एसो. सिएशन ऑफ इंडिया के डॉ सुब्बा राव पावुलुरी, और स्काईरूट एयरोस्पेस के श्री कुणाल गुप्ता जैसे वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए।

लेफ्टिनेंट जनरल नरसिम्हन ने सिविल. –मिलिट्री फ्यूजन (सीएमएफ) और चीन की अंतरिक्ष क्षमताओं पर फोकस करते हुए सत्र की शुरुआत की। उन्होंने सरकार के नियंत्रण तथा उद्योगों, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत तक व्याप्त सीएमएफ की निगरानी के बारे में बताया।

डॉ सुब्बा राव पावुलुरी ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रारंभिक चरण के अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखे जाने और उद्योग के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में इसरो के योगदान के उल्लेख से की। इसके बाद उन्होंने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी और उपग्रह निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।

सत्र के अंतिम वक्ता स्काईरूट एयरोस्पेस के कुणाल गुप्ता थे। उन्होंने अंतरिक्ष उद्योग का संक्षिप्त विवरण देते हुए बताया कि कैसे अंतरिक्ष समाधान सतत विकास लक्ष्यों के साथ सुदृढ़ता से संबद्ध हैं। इसके अलावा उन्होंने स्काईरूट एयरोस्पेस के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

डॉ भास्कर बालकृष्णन ने समापन भाषण में वेबिनार का सारांश प्रस्तुत किया तथा एफआईएसडी और आरआईएस की ओर से सभी वक्ताओं और उपस्थित लोगों का आभार प्रकट किया। ■

43वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान

मस्तिष्क विज्ञान पर अनुसंधान में निवेश का औचित्य क्या है?

43वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान इंफो. सिस के सह–संस्थापक और पूर्व उपाध्यक्ष, एक्सिलोर वेंचर्स के अध्यक्ष और सीआईआई एआई फोरम और सीआईआई स्टार्ट–. अप काउंसिल के अध्यक्ष श्री सेनापति गोपालकृष्णन (क्रिस) ने 28 अप्रैल 2022 को "मस्तिष्क विज्ञान पर अनुसंधान में निवेश का औचित्य क्या है?" विषय पर दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन ने की। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया, उनके बाद इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक श्री सुनीत टंडन ने संक्षिप्त भाषण दिया।

अपने बहुत ही सहज संबोधन में श्री गोपालकृष्णन ने मस्तिष्क विज्ञान जैसे

श्री सेनापति गोपालकृष्णन

रोमांचक क्षेत्र पर अनुसंधान करने के महत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्तिष्क विज्ञान पर इस तरह के अनुसंधान में बड़ी मात्रा में डेटा उभरने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि मस्तिष्क कैसे विकसित होता है, उम्र बढ़ने के दौरान या बीमारी के समय इसमें क्या परिवर्तन होते हैं।

श्री गोपालकृष्णन ने भारत के साथ ही साथ दुनिया भर में मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के रोगियों की बढ़ती संख्या पर भी गंभीर चिंता प्रकट की।

उन्होंने हाल ही में आईआईटी–मद्रास में सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर की स्थापना के माध्यम से भारत में मस्तिष्क अनुसंधान को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया, ताकि हाई–रिज़ॉल्यूशन ब्रेन इमेजिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेलुलर और कनेक्टिविटी स्तरों पर मानव मस्तिष्क की मैपिंग के लिए एक महत्वाकांक्षी वैश्विक परियोजना को बल प्रदान किया जा सके। ■

44वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान

निरंतरता की नीतिगत चुनौतियां

44वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक मामलों के पूर्व अवर महासचिव और टेरी की शासी परिषद के अध्यक्ष श्री नितिन देसाई, ने 28 जून, 2022 को "निरंतरता की नीतिगत चुनौतियां" विषय पर दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता टेरी की महानिदेशक डॉ विभा धवन ने की। स्वागत भाषण आरआईएस में साइंस डिप्लोमेसी फेलो डॉ भास्कर बालकृष्णन ने दिया, उनके बाद इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक श्री सुनीत टंडन ने संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री देसाई ने अपने सहज संबोधन की शुरुआत 1980 के दशक से सतत विकास के विचार के क्रमिक विकास की पड़ताल से की, जब ब्रंटलैंड आयोग (पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में स्थापित विश्व आयोग) ने "हमारा साझा भविष्य" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरंतरता के विचार में मूल रूप से तीन चीजों को एक साथ जोड़ना शामिल हैः आर्थिक आयाम,

श्री नितिन देसाई

सामाजिक आयाम और पर्यावरणीय आयाम। निरंतरता के लिए आज पर्यावरण की दृष्टि से हम जिस सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह है जलवायु परिवर्तन। जलवायु के मुद्दे पर आवश्यक बिंदु कार्बन का उत्सर्जन है। ऐसा अक्सर दोहराया जाता है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो सच है क्योंकि भारत का उत्सर्जन 1990 में लगभग 600 मिलियन टन से बढ़कर 2019 में लगभग 2.6 बिलियन टन के करीब हो गया। भारत ने प्रतिक्रिया दी है और जलवायु प्रक्रिया में अपनी प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं। प्रतिबद्ध ताओं के संबंध में भारत की नवीनतम स्थिति यह है कि उसने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 1बिलियन टन की कमी लाने, जीडीपी की कार्बन गहनता में 45 प्रतिशत तक कमी लाने, गैर–जीवाश्म बिजली क्षमता को 500जीडब्ल्यू तक बढ़ा. ने और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बिजली का हिस्सा 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही है, जो काफी सराहनीय है। श्री देसाई ने स्वीकार किया कि इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। श्री देसाई ने बेहतर सतत भविष्य के लिए प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने की धारणा को वापस लाने की आवश्यकता पर बल दिया। ■

ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत–ईयू सहयोग: सतत ऊर्जा संक्रमण की ओर

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय तथा यूरोपीय संघ (ईयू)–भारत पर ईयू–यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा (यूरोपीयन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस) के सहयोग से 2 जून, 2022 को 'ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत–ईयू सहयोग: सतत ऊर्जा संक्रमण की ओर' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत में यूरोपीय संघ के महामहिम राजदूत श्री उगो एस्टुटो ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे जैसी पहल सहित सहयोग को गहन और व्यापक बनाने और इस तरह पर्यावरण के अनुकूल संक्रमण में तेजी लाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अपर सचिव डॉ वंदना कुमार ने कहा कि ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भारत में इलेक्ट्रोलाइजर सहित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपला. इन बनाने और विनिर्माण सुविधाओं की आवश्यकता है ताकि आपूर्ति पक्ष को सशक्त बनाया जा सके।

विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (यूरोप पश्चिम) श्री संदीप चक्रवर्ती ने इस अवसर

आयोजन में उपस्थित विशिष्ट प्रतिभागी

पर अपने संबोधन में कहा कि अब मुख्य चुनौती संयुक्त ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की शुरूआत करना, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के लिए बाजार तलाशना तथा साथ ही प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण में चुनौतियों (भंडारण और परिवहन से संबंधित मुद्दों सहित) का समाधान करना है।

ऊर्जा महानिदेशालय, यूरोपीय आयोग के प्रधान सलाहकार श्री ट्यूडर कॉन्स्टेंटिनेस्कु ने इस बात को रेखांकित किया कि यूरोपीय संघ की आरईपॉवरईयू प्लान का उद्देश्य एक सुदृढ़ ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में तेजी लाना और टिकाऊ साझेदारियां बनाना है।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों को कवर किया गया : (1) भारत में, विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइज़र विनिर्माण साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संभावित संयुक्त पायलट परियोजनाओं की पहचान करना, – जिन्हें प्रारंभिक–अवस्था के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्षों द्वारा जल्दी शुरू किया जा सकता है; (2) व्यवहार्य परियोजनाओं की दीर्घकालिक पाइप लाइन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और कुशल तंत्र विकसित करना और एक मजबूत ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना; (3) निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत और नियामक परिवर्तनों का पता लगाना; (4) पायलट परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन जुटाने के तरीकों की योजना बनाना; (5) ग्रीन हाइड्रोजन के वित्तपोषण में शामिल प्रमुख जोखिमों का का हल निकालना; (6) जोखिम–शमन में विकास वित्त संस्थानों की भूमिका। ■

स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद–प्रशांत के लिए कनेक्टिविटी सहयोग: संवर्धित कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक लचीलेपन का निर्माण

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में जापान के दूतावास, आरआईएस और आरआईएस में आसियान–इंडिया सेंटर, नई दिल्ली के साथ साझेदारी में 8 अप्रैल, 2022 को इंडो–पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (आईपीओआई) के कनेक्टिविटी आधार पर स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद–प्रशांत के लिए कनेक्टिविटी सहयोग: संवर्धित कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक लचीलेपन का निर्माण' विषय पर संगोष्ठी के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। यह संगोष्ठी वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने उद्घाटन भाषण दिया, जबकि आरआईएस के अध्यक्ष डॉ मोहन कुमार ने विशेष भाषण दिया। महामहिम राजदूत, असाधारण और पूर्णाधिकारी, जापान दूतावास, नई दिल्ली सातोशी सुजुकी ने उद्घाटन भाषण दिया। राजदूत सौरभ कुमार, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रमुख भाषण दिया। महामहिम राजदूत सतोशी सुजुकी ने अपने उद्घाटन भाषण में हाल ही में भारत को अपने हिंद–प्रशांत विजन में एक प्रमुख साझेदार के रूप में महत्व देते हुए एक शिखर बैठक के लिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की 19 मार्च, 2022 की भारत यात्रा के बारे में विचार प्रकट किए। 17 मार्च, 2021 को आयोजित कनेक्टिविटी पर संगोष्ठी के पहले संस्करण से ही राजदूत सतोशी सुजुकी ने पिछले एजेंडे के आधार पर आगे बढ़ते हुए स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद–प्रशांत पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम को शामिल करने; संवर्धित कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक लचीलेपन के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। राजदूत सौरभ कुमार ने अपने प्रमुख भाषण में जापान–भारत द्वारा अनेक कनेक्टिविटी परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग को उपयोगी बनाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।

वेबिनार में दो सत्र थे: प्रथम सत्र गुणवत्ता अवसंरचना और आर्थिक लचीलेपन पर आयोजित किया गया था, जिसमें आघातों को अवशोषित कर लचीली अर्थव्यवस्था के निर्माण में अच्छी गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे के महत्व पर चर्चा की गई। डिजिटल कनेक्टिविटी पर आयोजित द्वितीय सत्र में हिंद–प्रशांत को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर बल दिया गया। ■

भारत, यूरोपीय संघ का तीसरे देशों में कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित साझेदारी बढ़ाने पर विचार

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू), निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने वाले जो. खिम–शमन उपायों के माध्यम से तीसरे देशों में कनेक्टिविटी परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने सहित कनेक्टिविटी क्षेत्रों में अपनी साझेदारी बढ़ाने के प्रति उत्साहित हैं। इस संबंध में, आरआईएस ने 27 अप्रैल 2022 को एमईए, भारत, ईयू एक्सटर्नल एक्शन सर्विस और यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) के साथ 'भारत–ईयू कनेक्टिविटीः नए संदर्भ, नए क्षितिज' का आयोजन किया।

प्रोफ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी महामहिम राजदूत रोमाना व्लाहुतिन का स्वागत कर रहे हैं।

आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने आरआईएस द्वारा प्रारंभ की गई कनेक्टिविटी वेबिनार श्रृंखला का उल्लेख किया तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच कनेक्टिविटी साझेदारी को आगे बढ़ाने में आरआईएस में स्थापित वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी) की द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर प्रकाश डाला। विदेशी, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ), यूके और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से जीडीसी भारत के विकास के अनुभव को अफ्रीका सहित ग्लोबल साउथ तक ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जीडीसी के काम को मजबूती देने के लिए यूरोपीय संघ साथ काम कर सकता है।

यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस (ईईएएस) में कनेक्टिविटी के लिए एम्बेसेडर एट लार्ज राजदूत रोमाना व्लाहुतिन ने कहा, "हम यह पता लगाना चाहते हैं कि हम दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका में तथा संभवतः यूरोप के करीब कुछ क्षेत्रों में भी अपनी क्षमताओं को सर्वोत्तम रूप से कैसे जोड़ सकते हैं।"

विदेश मंत्रालय, भारत में संयुक्त सचिव (यूरोप पश्चिम डिवीजन) श्री संदीप चक्रवर्ती ने इस अवसर पर कहा कि कनेक्टिविटी के संबंध में भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ता राजनीतिक संयोजन है, जो नेताओं के स्तर सहित कई स्तरों पर एक साथ काम करने की राजनीतिक इच्छा को दर्शाता है। द्विपक्षीय एफटीए के लागू होने पर निजी पूंजी को आकर्षित करने और कारोबारी संबंधों को बेहतर बनाने की क्षमता के संदर्भ में इस साझेदारी को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि अपनी ग्लोबल गेटवे रणनीति के माध्यम से यूरोपीय संघ भारत और दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भी विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक अन्य प्रस्ताव यूरोपीय संघ की मदद से त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष (भारत के साझेदार विकसित देशों के साथ काम करने के लिए नियत) की प्रतिकृति बनाना था, ताकि तीसरे देशों में परियोजनाओं को विकसित करने के लिए भारतीय विशेषज्ञता, प्रतिभा और उद्यमिता को लाया जा सके। अधिकारी ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ तीसरे देशों में भारत के डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की सफलता को दोहराने के लिए भी भागीदार हो सकते हैं।

यूरोपीय निवेश बैंक के उपाध्यक्ष श्री क्रिश्चियन केटेल थॉमसन ने जिन मुद्दों पर चर्चा की, उनमें जलवायु के लिए वित्त बढ़ाने की आवश्यकता, निजी प्रतिभागियों को आकृष्ट करने के लिए परियोजनाओं के जो. खिम में कमी लाने की अहमियत, साथ ही साथ सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे।

इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रकट करने वाले अन्य लोगों में आरआईएस की शासी परिषद और सामान्य निकाय के सदस्य डॉ शेषाद्री चारी, इंडिपेंडेंट ग्रीन हाइड्रोजन एसोसिएशन के महानिदेशक श्री शशि शेखर, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पी.आर. जयशंकर, प्रबंध निदेशक – इंडिया और – निदेशक, रैम्बोल इंजीनियरिंग सेंटर सुश्री विद्या बासरकोड, स्नम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री मैनेजर और सीईओ श्री डेविड सिरेली, मार्सक इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के हैड ऑफ पब्लिक अफेयर्स श्री संजय तिवारी और इंडिया इंटरनेट फंड के मैनेजिंग पार्टनर श्री अनिरुद्ध सूरी शामिल थे। आरआईएस में विजिटिंग फेलो, श्री अरुण नायर ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। ■

आसियान–भारत आर्थिक संबंधों की तीसवीं वर्षगांठ पर वेबिनार

आसियान–भारत रणनीतिक साझेदारी की तीसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, आरआईएस में आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) आसियान–भारत संबंधों में निरंतर मौजूद चुनौतियों और उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्चुअल माध्यम से वेबिनार आयोजित कर रहा है। इस श्रृंखला का दूसरा वेबिनार 22 अप्रैल, 2022 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। वक्ताओं ने आर्थिक आधार पर भारत और आसियान के बीच वर्तमान संबद्धताओं पर चर्चा की। वक्ताओं ने प्रकट हो रहे वैश्विक राजनीतिक परिदृश्यों के मद्देनजर कोविड–19 महामारी से उबरने, आसियान–भारत एफटीए प्रक्रिया की समीक्षा, आरसीईपी, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, साझेदारी को मजबूत बनाने में डिजिटलीकरण की भूमिका जैसे मुद्दों को कवर किया। वक्ताओं ने अगले दशक में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए इस क्षेत्र की प्राथमिकताओं की भी पहचान की। ■

आसियान–इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक–टैंक का सातवां सम्मेलन

आसियान–इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक–टैंक (एआईएनटीटी) का सातवां दौर 12 मई, 2022 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ। कंबोडियन इंस्टीट्यूट फॉर कोऑपरेशन एंड पीस (सीआईसीपी), नोम पेन्ह ने रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (आरआईएस), नई दिल्ली में आसियान–इंडिया सेंटर के साथ एक भागीदार संगठन के रूप में हाथ मिलाया है। एआईएनटीटी आसियान इंडिया फंड द्वारा समर्थित और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार तथा जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय मिशन के प्रोत्साहन से लाभान्वित है। दूसरे दिन का कार्यक्रम 13 मई 2022 को आयोजित किया गया।

एआईएनटीटी के 7वें दौर में विशिष्ट प्रतिभागी

भारत के माननीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह और कंबोडिया के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय में माननीय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डॉ कुंग फोक ने क्रमशः उद्घाटन भाषण और प्रमुख भाषण दिया।

आरआईएस के अध्यक्ष डॉ मोहन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया कोविड–19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के दोहरे संकट का सामना कर रही है। राजदूत कुमार ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में, आसियान और भारत दोनों द्वारा परस्पर उच्च विश्वास कायम रखने पर गौर करते हुए द्विपक्षीय के साथ–साथ बहुपक्षीय संबंधों को व्यापक बनाने तथा दुनिया के लिए टिकाऊ साझेदारी कायम करने के और अधिक तौर–तरीकों का सृजन करने के लिए तकनीकी सहयोग को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। कंबोडिया के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय में माननीय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डॉ कुंग फोक ने भारत को आसियान का एक महत्वपूर्ण भागीदार करार दिया। उन्होंने वर्तमान साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत आसियान–भारत समग्र रणनीतिक साझेदारी दस्तावेज के मसौदे की भी सराहना की।

भारत के माननीय विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आसियान, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। 7वें एआईएनटीटी में क्षेत्रों के लिए कोविड–19 के बाद की रिकवरी पर रचनात्मक बातचीत किया जाना निर्धारित किया गया था। हिंद–प्रशांत में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में आसियान को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। वर्तमान संदर्भ में आसियान–भारत साझेदारी के तीन महत्वपूर्ण पहलू–स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के अनुकूल सतत भविष्य हैं। हिंद–प्रशांत देशों को सार्थक स्वास्थ्य साझेदारी कायम करने में सहायता देने के लिए भारत वैक्सीन मैत्री और क्वाड वैक्सीन कूटनीति जैसी पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भारत ने इस क्षेत्र के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा को अपनाते हुए हरित और टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आसियान भारत हरित कोष जैसी पहल भी की है।

शेष सत्रों में, आसियान के सभी सदस्य देशों के वक्ताओं ने अपनी बात रखी और भारत ने 'कोविड –19 के बाद रिकवरी : आसियान–भारत साझेदारी के लिए क्षेत्रीय सहयोग का एजेंडा' विषय पर दो दिवसीय कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उन्होंने टिकाऊ बहाली, स्वास्थ्य, एसडीजी, एमएसएमई, कनेक्टिविटी में सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन पर सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। ■

आसियान और भारत के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक साझेदारी

आसियान और भारत के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक साझेदारी पर 30 जून, 2022 को वेबिनार आयोजित किया गया। एआईसी के समन्वयक डॉ प्रबीर डे ने अपने उद्घाटन भाषण में आसियान–भारत संबंधों के बदलते स्वरूप और संपन्न की गई गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत में इंडोनेशिया गणराज्य की असाधारण और साधिकार राजदूत महामहिम इना हाग्निनिंग्टस कृष्णमूर्ति ने वेबिनार में भारत और आसियान के बीच "रणनीतिक विश्वास" पर केंद्रित विशेष भाषण दिया। उन्होंने आसियान सामाजिक–सांस्कृतिक सामुदायिक ब्लूप्रिंट की तर्ज पर आसियान और भारत के बीच सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण–पश्चिम प्रशांत अध्ययन, के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर घोषाल ने अपने विशेष भाषण में आसियान और भारत के बीच भू–सभ्यतागत संपर्क पर विचार प्रकट किए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की शताब्दी अध्यक्ष प्राध्यापक, प्रोफेसर लिपि घोष ने वेबिनार की अध्यक्षता की। वक्ताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्राध्यापक प्रोफेसर पारुल पंड्या धर, मनीला में फिलीपींस विश्वविद्यालय के एशियन सेंटर में प्राध्यापक प्रोफेसर जोएफ बी संतरिता, बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ राजीव रंजन चतुर्वेदी और वियतनाम के हा नोई में यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमेनिटीज (वीएनयू) के भारतीय अध्ययन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ दो थू हा शामिल थे। वक्ताओं ने आसियान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक विशिष्टताओं और सभ्यतागत विरासतों के महत्व का संज्ञान लिया, जिन्हें समकालीन उपयोग के लिए अनुवाद और रूपांतरित करने की आवश्यकता है। ■

दुर्लभ मृदा तत्वों तक पहुंच और विनिर्माण की संभावनाए

भारतीय दुर्लभ मृदा क्षेत्र

भारत समृद्ध आरईई भंडार से संपन्न है। लगभग 7 मिलियन टन आरईई रिजर्व के साथ, भारत वैश्विक आरईई भंडार के 5 प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी है, जो दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा भंडार है। दिलचस्प बात तो यह है कि भारत भी आरईई के महत्व को पहचानने वाले शुरुआती देशों में से एक रहा है। 1950 के दशक में इसने आरईई के खनन और प्रसंस्करण के लिए इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल) की स्थापना कर घरेलू आरईई उत्पादन क्षमता विकसित करने के प्रयास शुरू किए। समृद्ध भंडार और आंरभिक दौर में शुरुआत के बावजूद, भारत किसी महत्वपूर्ण आरईई उद्योग को विकसित करने में सक्षम नहीं हो सका है और वैश्विक आरईई बाजार में इसका हिस्सा भी नगण्य रहा है। विडंबना तो यह है कि आरईई के उत्पादन के लिए स्थापित किए गए आईआरईएल ने वास्तव में कभी आरईई उत्पादन पर ध्यान ही केंद्रित नहीं किया। इसकी बजाय, आईआरईएल ने थोरियम और इल्मेनाइट, जिरकोन, रूटाइल आदि जैसे अन्य खनिजों को अधिक महत्व दिया। इसके परिणामस्वरूप, वर्षों से, भारत में आरईई उत्पादन 2018–19 (एमओएम 2020) में 4215 टन तक बढ़ने से पहले लगभग 2000 टन पर स्थिर रहा। आरईई की अत्यधिक कम घरेलू आपूर्ति ने डाउनस्ट्रीम आरईई उद्योग की भारत में अनुपस्थिति वस्तुतः सुनिश्चित कर दी। इसके कारण भारतीय निर्माताओं को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीनरी, सौर पैनल आदि की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीन से तैयार आरईई के आयात पर निर्भरता के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे व्यापार घाटे में भारी वृद्धि हुई।

भारत द्वारा अपनी आरईई क्षमता से अवगत होने में अक्षम रहने के लिए मुख्य रूप से निष्क्रिय सरकारी रवैये को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आरईई की खोज और प्रसंस्करण वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा है और इसलिए विकास के प्रारंभिक चरण में स्पष्ट नीति और वित्तीय सहायता के संदर्भ में सरकारी समर्थन की आवश्यकता है। हालांकि, आरईई के महत्व की पहचान हो जाने के बावजूद, भारत सरकार आरईई क्षेत्र के विकास के लिए एक स्पष्ट नीति या रोड मैप तैयार करने में विफल रही। आरईई के लिए एक अलग नीति बनाने के बजाय, सरकार ने आरईई को परमाण J खनिजों के साथ जोड़ दिया, इससे राज्य का एकाधिकार सुनिश्चित हो गया तथा विदेशी और निजी घरेलू निवेशक दूर रहे, जिससे आरईई क्षेत्र गतिहीन हो गया। जापान जैसे वैश्विक तकनीकी अगुआ ने भारत से आरईई प्राप्त करने का प्रयास किया। 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री आबे ने भारत में 2000 टन आरईई का उत्पादन करने और उसे जापान को निर्यात करने संबंध ी समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, राज्य के एकाधिकार, प्रौद्योगिकी की कमी, पर्यावरण मंजूरी की बाधाओं और किसी व्यवहार्यता अंतर निधि के अभाव में आज तक कुछ भी कार्यान्वित नहीं हो पाया है।

भारत: एक प्रमुख आरईई निर्माता

चीन से बढ़ते मोहभंग ने भारत के लिए उत्साहजनक अवसर के द्वार खोल दिए हैं। चीन पर निर्भरता कम करके हाई–टेक उत्पाद की एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में उभरा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूरोपीय संघ सभी अपनी हिंद–प्रशांत रणनीतियों के साथ सामने आए हैं, जो अन्य उद्देश्यों के साथ–साथ आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन/विविधता पर भी बल देती हैं। इनमें से कुछ देशों ने अपनी कंपनियों पर चीन पर निर्भरता कम करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि, इन अलग–अलग प्रयासों के सीमित परिणाम मिले हैं। इसलिए, हाई–टेक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए ध्यानपूर्वक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इन देशों के नीति निर्माताओं ने इसे महसूस किया है और इसके परिणामस्वरूप, भारत–जापान–ऑस्ट्रेलिया, भारत–फ्रांस–ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय सहयोग और चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद के रूप में आपूर्ति के लचीलेपन के लिए बहु–राष्ट्रों के सहयोग को गति मिली है। भारत–जापान–ऑस्ट्रेलिया एक कदम आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने औपचारिक रूप से एक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) की शुरूआत की है, जो आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त व्यापार और निवेश विविधीकरण उपायों के साथ–साथ निवेश को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों और क्रेता–विक्रेता की बैठकों के कार्यक्रमों की परिकल्पना करती है।

चीन पर तकनीकी निर्भरता कम करने और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन की बढ़ती मांग भारत के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करती है, जिसके पास दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा आरईई भंडार है। चीनी अनुभव को देखते हुए भारत भी अपने आरईई भंडार का उपयोग उन्नतिशील उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने के लिए कर सकता है। चीन पर तकनीकी निर्भरता कम करने के लिए भारत के लिए आरईई केंद्रित दृष्टिकोण का चयन करने के लिए मौजूदा परिस्थितियां सबसे अनुकूल हैं। दुनिया में तकनीकी दृष्टि से अगुआ देश चीन के बाहर आरईई आपूर्ति बनाने की सक्रिय रूप से कोशिश कर रहे हैं। जापान के वित्तीय सहयोग ने ऑस्ट्रेलियाई फर्म को आरईई उत्पादन फिर से शुरू करने में सहायता की है। अमेरिका भी आरईई का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग कर रहा है। इन प्रयासों ने ऑस्ट्रेलिया को 2018 में वैश्विक आरईई का 15 प्रतिशत उत्पादन करने में मदद की है, जबकि उसके पास वैश्विक आरईई भंडार का सिर्फ 2.5 प्रतिशत है। दूसरी ओर भारत के पास विश्व के ज्ञात आरईई भंडार का 5 प्रतिशत से अधिक अंश मौजूद है। हालांकि, इसका उत्पादन लगभग 3000 टन पर स्थिर बना हुआ है।

भारत और हिंद–प्रशांत में उसके उभरते रणनीतिक साझेदारों के लिए आरईई के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में सहयोग करने की अपार संभावना मौजूद है। आरईई के उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया एक आदर्श साझेदार है। इसी तरह, जापान, अमेरिका और फ्रांस को आरईई उत्पादन परियोजना में व्यवहार्यता अंतर को पाटने के लिए भारत के साथ वित्तीय सहयोग करने में खुशी होगी। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगने से पहले भारत को अपने यहां आवश्यक सुधार करने की आवश्यकता है। भारत में अपस्ट्रीम आरईई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो चरणों की आवश्यकता है। पहला, भारत को वास्तविक उद्देश्यों के साथ आरईई क्षेत्र के लिए तत्काल एक स्पष्ट नीति तैयार करनी चाहिए। दूसरा, इसे परमाणु खनिज रियायत अधिनियम (2016) में संशोधन करना चाहिए, जिसने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए 0.75 प्रतिशत से अधिक मोनाज़ाइट (आरईई का स्रोत) होने के बावजूद सभी बीच सैंड माइन्स को आरक्षित कर दिया है। अगर इन दो उपायों को तुरंत अपना लिया जाता है तो इनमें भारत को एक प्रमुख आरईई उत्पादक में परिवर्तित करने की क्षमता विद्यमान है। अपस्ट्रीम आरईई उद्योग का विकास आर्थिक रूप से अधिक मूल्यवान डाउनस्ट्रीम विनिर्माण को प्रोत्साहित कर सकता है जिससे आत्मनिर्भर भारत बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

(आरआईएस में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ पंकज वशिष्ठ द्वारा तैयार किए गए आरआईएस नीति सारांश संख्या 106 के अंश।)

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- यूएनईएससीएपी–एपीसीटीटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चीन और गुआ. ंगज़ो विश्वविद्यालय द्वारा 30 जून 2022 को 4आईआर प्रौद्योगिकियों के नवाचार, हस्तांतरण और प्रसार विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में '4आईआर प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण और उन्हें अपनाने की रणनीतियों और व्यापार मॉडल को सक्षम बनाना' पर प्रस्तुति दी।
- कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस द्वारा 27 जून 2022 को भारत की भ. ागीदारी और निष्कर्ष; जलवायु के मुद्दों में समानता का प्रश्न और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना तथा जी–20 की अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले भारत की भागीदारी की प्रासंगिकता पर पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया।
- आईसीडब्ल्यूए द्वारा 15 जून 2022 को भारत की विकास साझेदारीः विस्तारशील परिदृश्य विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'भारत की विकास भागीदारी' पर प्रस्तुति दी।
- मुंबई में आईजीआईडीआर द्वारा 14 जून 2022 को आयोजित 21वें आईएएसएसआई वार्षिक सम्मेलन में 'इंडियन सोशल साइंस रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी–थिंक टैंक कनेक्ट : द वे फॉरवर्ड' पर तरलोक सिंह स्मृति व्याख्यान दिया।
- इंडिया राइट्स नेटवर्क इंडिया एंड द वर्ल्ड पत्रिका द्वारा सेंटर फॉर ग्लोबल इंडिया इनसाइट्स (सीजीआईआई) के सहयोग से 9 जून 2022 को आयोजित 'द क्वाड वे : ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड' पर वेबिनार को संबोधित किया।
- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 7 जून 2022 को 'स्वास्थ्य और विकास को आगे बढ़ाने के लिए डि. जिटल नवाचार – भारत के डिजिटल सार्वजनिक सामान दुनिया को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं' विषय पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा द्वारा 5 जून 2022 को 3एस इंटरनेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में आयोजित "स्वदेशी, आत्म–निर्भर एंड सस्टेनाबिलिटीः कंवर्जेंसेज एंड वे फॉरवर्ड" पर प्रमुख भाषण दिया।
- आईएलआर स्कूल ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और जीआरएएएम द्वारा 28 मई 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित 3पीई–पब्लिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम इवेल्यूएशन कार्यशाला के चौथे संस्क. रण के दौरान "बड़े पैमाने की सरकारी परियोजनाओं की निगरानी" पर विशेष व्याख्यान की अध्यक्षता की।
- जी–20 की संरचना के भीतर तथा इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय, डी20 और टी20 तथा बी20 के आधिकारिक संबद्ध समूहों के सहयोग से 24 मई 2022 को बर्लिन में आयोजित वर्चुअल सेमिनार में बुनियादी ढांचे में भावी निवेश के बारे में साझा दृष्टिकोण का निर्माणः टी 20, बी 20, डी 20 का योगदान से संबंधित सत्र में 'बहाली और सुरक्षित, सतत भविष्य के लिए बलों के साथ जुड़ना : जी–20 में उच्च प्रभाव वाली सतत ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बहुपक्षीय रोडमैप का आकलन करना' विषय पर चर्चा में भाग लिया।
- ग्लोबल सॉल्यूशन इनिशिएटिव और डीआईई द्वारा 23 मई 2022, को बर्लिन में आयोजित 'थिंक 7 समिट : प्रतिस्पर्धी भू–राजनीतिक वातावरण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना' में 'नए भू–राजनीतिक वातावरण में जी–7 की भूमिका' पर विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया।
- ग्लोबल पार्टनर्शिप इनिशिएटिव ऑन इफैक्टिव ट्राइएंगुलर को–ऑपरेशन (जीपीआई) की ओर से 23 मई 2022 को बर्लिन में ट्राइएंगुलर को–ऑपरेशन विद् एशियाः स्टेप्स फ्रॉम पोलिटिकल सपोर्ट टू प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन' विषय पर अनौपचारिक रणनीतिक विचार–. विमर्श में भाग लिया।
- ग्लोबल सॉल्यूशन इनिशिएटिव और डीआईई द्वारा 23 मई 2022, को बर्लिन में आयोजित 'थिंक 7 समिट : प्रतिस्पर्धी भू–राजनीतिक वातावरण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना' में ' जी–7 को जी–20 के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिएघ' पर विषय पर पूर्ण अधिवेशन में पैनल चर्चा में भाग लिया।
- समान विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रिक्स के लिए बौद्धिक समर्थन को सुदृढ़ करना थीम पर आयोजित 14वें ब्रिक्स एकेडेमिक फोरम 2022 में चाइना काउंसिल फॉर ब्रिक्स थिंक टैंक कोऑपरेशन द्वारा 20 मई 2022 को 'वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करना और वैश्विक आर्थिक शासन प्रणाली में सुधार लाना' विषय पर आयोजित सत्र में भाषण दिया।
- सीपीसी केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग, चाइना काउंसिल फॉर ब्रिक्स थिंक टैंक और चाइना एनजीओ नेटवर्क फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से 19 मई 2022 को आयोजित किए गए ब्रिक्स राजनीतिक दलों, थिंक टैंक और सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन फोरम ऑन सॉलिडेरिटी एंड कोऑपरेशन टुअर्ड्स कॉमन डेवलपमेंट और ब्राइटर फ्यूचर के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया।
- सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज के समन्वय से वाणिज्य विभाग द्वारा 18 मई 2022 को आयोजित एमसी–12 की तैयारी में डब्ल्यूटीओ मुद्दों पर परामर्श बैठक में भाग लिया।
- आईसीएसएसआर द्वारा 15 मई 2022 को आयोजित "अर्थशास्त्र को समझने की चुनौतियां" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत की विकास संभावनाओं पर एक सत्र में भाषण दिया।
- स्पेशल इवेंट 3 में पैनलिस्टः साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (एसटीआई फोरम) द्वारा इंटर एजेंसी टास्क टीम ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर एसडीजी (आईएटीटी) के सहयोग से 6 मई 2022 को आयोजित किए गए ''सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के पूर्ण कार्यान्वयन को आगे बढ़ाते हुए कोरोना वायरस रोग (कोविड–19) से रिकवरी के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार'' पर एसडीजी के लिए एसटीआई पर सातवें वार्षिक बहु–हितधारक फोरम में राष्ट्रीय क्षमताओं और पार्टनरशिप इन एक्शन फॉर एसटीआई4एसडीजी रोडमैप का समर्थन।

- "एसटी की कानूनी स्थिति; उनकी पह. चान और भविष्य" पर ग्लोबल आस्पेक्ट ऑफ द नेशनल विमर्श के चौथे सत्र में 1 मई 2022 को 'भारत को आदिवासी लोगों की बहस पर अत्यावश्यकता के साथ क्यों गौर करना चाहिए' विषय पर विशेष भाषण दिया।
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजी. जीपीए), भोपाल और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईस. ीएसएसआर) द्वारा 28–29 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित मध्य प्रदेश पीएचडी कोलोक्वियम, 2022 में उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और अनुसंधान डिजाइन की रणनीतियों पर सत्र की अध्यक्षता की।
- श्री बालाजी विद्यापीठ, एबीएलई और स्टीमसन द्वारा संयुक्त रूप से 26 अप्रैल, 2022 को बेंगलुरु में 'सुरक्षित व्यापार और जैव प्रौद्योगिकी का हस्तांतरणः भारत में विनियम और अच्छी पद्धतियां' विषय पर आयोजित कार्यशाला में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के व्यापार, निवेश और नवाचार की दिशा के बारे में प्रस्तुति दी।
- ग्रेटर नोएडा में 23 अप्रैल 2022 को शारदा यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन (यूपीयूईए) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 17वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में आजादी के 75 वर्ष पर शिक्षा और अर्थशास्त्र के शिक्षण में व्यापार को कैसे एकीकृत किया जाए पर प्रस्तुति दी।
- आयुष मंत्रालय द्वारा 20 अप्रैल 2022 को गांधीनगर में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में विचार–विमर्श से सहयोग तक : सरकार और उद्योग पर गोलमेज 3 में प्रस्तुति दी।
- आयुष मंत्रालय द्वारा 20 अप्रैल 2022 को गांधीनगर में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में विश्व के लिए भारतीय आयुष संभ. ावनाओं पर गोलमेज 2 में प्रस्तुति दी।
- क्षेत्रीय प्रौद्योगिकीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (एपीसीटीटी) द्वारा भारत की एसटीआई एजेंसियों और एपीसीटीटी के बीच 19 अप्रैल 2022 को आयोजित विचार–. विमर्श सत्र में भाग लिया।
- दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और अन्य द्वारा संयुक्त रूप से 15 अप्रैल 2022 चित्रकूट में आयोजित 'सतत विकास लक्ष्यों पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में 'एसडीजी' पर व्याख्यान दिया।
- भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा 13 अप्रैल 2022 को आयोजित भारत–. चीन व्यापार घाटा और उभरते व्यापार आख्यान विषय पर एक सत्र में भारत चीन व्यापार घाटा और व्यापक व्यापार आख्यान पर प्रस्तुति दी।
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान (एआईजी. जीपीए), भोपाल और प्रिया, नई दिल्ली द्वारा 8–9 अप्रैल 2022 को संयुक्त रूप से आयोजित सतत विकास के लिए साझेदारी और अनुभव साझा करने के लिए सीएसओ के साथ सम्मेलन' के दौरान उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और 'विकास संचार और लेखन' पर सत्र तथा 'सतत विकास के लिए साझेदारी और अनुभव साझा करनाः सीएसओ के साथ सम्मेलन' पर भी सत्र को संबोधित किया।
- संसद टीवी पर डिप्लोमैटिक डिस्पैच पर साप्ताहिक कार्यक्रम में 6 अप्रैल 2022 को माननीय प्रधानमंत्री देउबा की यात्रा के संदर्भ में संबंधों के आर्थिक आयामों पर भारत–नेपाल संबंधों पर रिकॉर्डिंग।

प्रोफेसर एस के मोहंती

- आसियान–भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ– दिल्ली संवाद XII:हिंद–प्रशांत में संबंधों में सुधार लाना में भाग लिया तथा 16 जून, 2022 को नई दिल्ली में भारत और आसियान के बीच आर्थिक साझेदारी को प्रगाढ बनाना :महामारी से उबरने के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण व्यापार, निवेश और मूल्य श्रृंखलाओं को सुगम बनाने से संबद्ध सत्र में द्विपक्षीय एफटीए की समीक्षा प्रस्तुति दी।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव में भाग लिया और विश्व महासागर दिवस, के अवसर पर 8 जून, 2022 नई दिल्ली में नीली अर्थव्यवस्था पर एक विशेष वार्ता के रूप में भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता पर एक प्रस्तुति दी।
- मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एमईआइ. –एनयूएस), सिंगापुर द्वारा 18 मई, 2022 को आयोजित पश्चिम एशियाः एशियाई प्रतिस्पर्धा के लिए एक नया क्षेत्र? पर वार्षिक सम्मेलन 2022 में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया और एक क्षेत्र के रूप में एमई सहित भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों पर जूम के माध्यम से प्रस्तुति दी।
- मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (एमईआइ. –एनयूएस), सिंगापुर द्वारा 17 मई, 2022 को आयोजित पश्चिम एशियाः एशियाई प्रतिस्पर्धा के लिए एक नया क्षेत्र? पर जूम वार्षिक सम्मेलन 2022 में चर्चा के बिंदुओं पर विचार–विमर्श में भाग लिया।
- नेपाल इंस्टीट्यूट फॉर इंट. रनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट (एनआईआईसीई) द्वारा 6 मई, 2022 को दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर वेबिनार में भाग लिया और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार सहयोग को बल देने पर एक प्रस्तुति दी।
- नीली अर्थव्यवस्था पर आरआईएस की कार्य प्रणाली के संबंध में नई दिल्ली में 28 अप्रैल, 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक।

डॉ प्रियदर्शी दाश

एसोसिएट प्रोफेसर

- टी20 इंडोनेशिया के सहयोग से आईए. सपीआई, इटली द्वारा 20–21 जून, 2022 को आयोजित ग्लोबल पॉलिसी फोरम में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए।

- 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए क्षितिज: जी–7 और जी–20 के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना' विषय पर 7 जून ,2022 को आरआईएस संगोष्ठी का आयोजन किया।
- आरआईएस द्वारा 6 जून,2022 को "जी–20 में विकास के मुद्दे: डीडब्ल्यूजी और टी20 में अवसर और संदर्भ" विषय पर आयोजित आरआईएस गोलमेज चर्चा में योगदान दिया।
- आरआईएस और भारत में आए यूरा. पीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत के सहयोग से 2 जून,2022 को "भारत ईयू कनेक्टि. विटी साझेदारी और वैश्विक प्रवेशद्व ार : निरंतर ऊर्जा संक्रमण के लिए ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग" विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई।
- जी–20 की संरचना के भीतर तथा इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय, डी20 और टी20 तथा बी20 के आधिकारिक संबद्ध समूहों के सहयोग से 'बहाली और सुरक्षित, सतत भविष्य के लिए बलों के साथ जुड़ना : जी–20 में उच्च प्रभाव वाली सतत ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बहुपक्षीय रोडमैप का आकलन करना' विषय पर 24 मई 2022 को आयोजित वर्चुअल सेमिनार में चर्चा में भाग लिया।

श्री राजीव खेर

विशिष्ट फेलो

- यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के वर्ल्ड ट्रेड इंस्टीट्यूट और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र, स्विट्जरलैंड के दूतावास द्वारा 30 जून,2022 को आयोजित व्यापार और जलवायु परिवर्तन पर वार्ता में भाग लिया।
- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र द्वारा 29 जून, 2022 को आयोजित बाहरी सब्सिडी के प्रति यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण पर व्यापार वार्ता में भाग लिया।
- विश्व व्यापार संगठन के हाल सुरक्षा उपायों के क्षेत्राधिकार के रुझानों पर सीडब्ल्यूएस द्वारा 20 जून, 2022 को आयोजित एक व्यापार वार्ता में भाग लिया।
- एस्या सेंटर द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फा. उंडेशन के सहयोग से 17–18 जून, 2022 को आयोजित डेटा मार्केट में प्रतिस्पर्धा के मुद्दों से संबंधित रणनीतिक योजना पर चर्चा में भाग लिया।
- डेलॉइट द्वारा 15 जून, 2022 को आयो. जित एशिया प्रशांत के लिए जलवायु और ईएसजी कारकों पर कार्यक्रम में भाग लिया।
- पीएचडीसीसीआई द्वारा 6 जून,2022 को आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया।
- डेलॉइट द्वारा 19 मई,2022 को आयो. जित 'डिजिटल फ्रंटियर: टेक्नोलॉजी एंड द बोर्ड' विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लिया।
- 17 मई, 2022 को 8वीं क्यूसीआई पीपीडी संचालन समिति की बैठक में सदस्य के रूप में भाग लिया।
- आईसीआरआईईआर–केएएस द्वारा 5 मई,2022 को आयोजित कोविड के बाद के विश्व में डब्ल्यूटीओ 2.0 पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- डेलॉइट द्वारा 4 मई, 2022 को आयोजित कार्यक्रम 'इन्फ्लैशन आउटलुक: हाउ कैन बोर्ड्स प्रीपेयर फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इन्फ्लैशन?' में भाग लिया।
- एयरटेल बैंक के बोर्ड की 2–3 मई, 2022 को आयोजित बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा 29 अप्रैल, 2022 को 'ऑन द व्हील्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इवॉल्विंग रोल्स ऑफ बोर्ड्स एंड इं. डपेंडेंट डायरेक्टर्स' विषय पर आयोजित पावर टॉक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 28 अप्रैल, 2022 को 'गियरिंग अप विद् ईएसजी : अ डिस्कशन ऑन इंडियाज़ ईएसजी प्लेबुक, प्रीपेयर्डनेस एंड एक्सपेक्टेशन्स' विषय पर आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- गुडइयर इंडिया लिमिटेड द्वारा 28 अप्रैल और 26 मई, 2022 को आयोजित 'जोखिम प्रबंधन समिति में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- कट्स द्वारा 27 अप्रैल, 2022 को 'क्या 'डेटा स्थानीयकरण' और 'राष्ट्रीय चैंपियन' दृष्टिकोण एक समावेशी डिजि. टल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा? विषय पर आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया।
- 20 अप्रैल, 2022 को एक्सप्लेन्ड लाइव : आफ्टर द वॉर: रशिया, द वेस्ट एंड इंडिया' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- एक्ज़िम बैंक द्वारा 8 अप्रैल, 2022 को आयोजित भारत –आस्ट्रेलिया : व्यापार और निवेश के आयाम का विकास' पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- 8–9 अप्रैल, 2022 को सीआईआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिट में भाग लिया।
- सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) द्वारा 6 अप्रैल, 2022 को 'फ्रॉम ग्रे टू ग्रीन :नेट–जीरो ट्रांसिशन ऑप्ट्यूनिटीज़ फॉर इंडिया' विषय पर आयोजित में प्रमुख संगोष्ठी में भाग लिया।

डॉ पी के आनंद

विजिटिंग फेलो

- 28 और 29 जून, 2022 को 'खाद्य सुरक्षा के लिए डिजिटल कृषि और ग्रामीण वित्त को बढ़ाना' शीर्षक पर आयोजित वाले जी–20 एडब्ल्यूजी वेबिनार में भाग लिया।
- एलपीईएम एफईबी यूआई के सहयोग से 2 जून, 2022 को इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ टी–20 इंडोनेशिया' के 'मैनेजिंग इलेवेटेड रिस्क्स ऑफ क्लाइमेट ट्रांसिजीशन'' शीर्षक से आयोजित टी–20 साइड इवेंट में भाग लिया।
- विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) के निमंत्रण पर 26 मई, 2022 को उज्बेकिस्तान द्वारा आयोजित 'शंघाई सहयोग संगठन की संरचना में 'गरीबी में कमी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में 'भारत में गरीबी में कमी' पर प्रस्तुति दी।

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) की ओर से 'निरंतर स्वस्थ आहार के लिए फल और सब्जियां (फ्रेश)' पर 25 मई, 2022 को आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
- यूएनईएससीएपी की ओर से 24 मई, 2022 को 'एशिया–प्रशांत में कार्बन तटस्थता लक्ष्य और सहयोग' विषय पर आयोजित साइड इवेंट में भाग लिया।
- यूएसएआईडी और आईएफपीआरआई की ओर से 24 मई, 2022 को 'सिंचाई निवेश नीतिः क्या पैमाना मायने रखता है?' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
- सामाजिक विकास परिषद और औद्यो. गिक विकास अध्ययन संस्थान (सीएसड. ीआईएसआईडी) द्वारा 12 मई, 2022 को 'भारत की औद्योगिक नीति और कार्य निष्पादन' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप द्वारा 11 मई, 2022 को 'एस्कलेटिंग द रोल ऑफ गैस इन एनर्जी ट्रांजिशन' विषय पर आयोजित जी–20 वेबिनार में भाग लिया।
- 27 से 29 अप्रैल, 2022 के दौरान 'जी–20 इंडोनेशियाः विंडोज़ फॉर रिकवरिंग टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर' विषय पर आयोजित किए गए जी–20 इंडोनेशिया के साइड इवेंट सीएसआईएस ग्लोबल डायलॉग 2022 में भाग लिया।
- एडीबी के सहयोग से 'आर्थिक दृष्टिकोणः प्रगति की संभावनाएं और क्षेत्रीय सहयोग' विषय पर 28 अप्रैल 2022 को आयोजित ईआरआईए कार्यक्रम में भाग लिया।
- डीआईई की सोशल कोहीशन टीम द्व ारा 26 अप्रैल 2022 को 'सामाजिक एकजुटता क्या, क्यों और कैसे? अफ्रीका में सामाजिक एकजुटताः हमारी क्या स्थिति है? हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं?' विषय पर एक ऑनलाइन संगोष्ठी में भाग लिया।
- अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास, मुंबई द्वारा 26 अप्रैल 2022 को 'रीमैन्युफै. क्चरिंगः द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआ. रआई) इंडोनेशिया द्वारा 21 अप्रैल 2022 को थिंक–20 (टी20) द्वारा एक साइड इवेंट के दौरान 'रिकवर स्ट्रॉन्गर थ्रू द जी20ः सस्टेनेबल लैंडस्केप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीस इन एग्रीकल्चर' विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया।
- जे–पाल द्वारा 19 अप्रैल 2022 को 'व्हेन एविडेंस मीट पॉलिसीः हेल्पिंग इंडियाज स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्ड टू पब्लिक हे. ल्थ चैलेंज' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- आईएफएडी द्वारा 11 अप्रैल 2022 को आयोजित 'ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणालियों में बदलाव : पोषण और पर्याव. रण कैसे तालमेल बैठाते हैं?' शीर्षक से चर्चा में भाग लिया।
- औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी) द्वारा 5 अप्रैल, 2022 को आयोजित 'भारत में हरित औद्योगीकरण' विषय पर नीतिगत गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फेलो

- जी–20 एजेंडा पर कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) और विकास कार्य समूह (डीडब्ल्यूजी) के बीच संयुक्त रूप से 28–29 जून 2022 को "खाद्य सुरक्षा के लिए डिजिटल कृषि और ग्रामीण वित्त को बढ़ाना" विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया। (आभासी)
- ओईसीडी और टी20 इंडोनेशिया की ओर से 20–21 जून 2022 को ग्लोबल पॉलिसी फोरम (जीपीएफ) पर कार्यक्रम में भाग लिया। (आभासी)
- टी20 इंडोनेशिया की ओर से 2 जून, 2022 को आयोजित 'जलवायु परिवर्तन के उच्च जोखिमों का प्रबंधन' विषय पर साइड इवेंट में भाग लिया।(आभासी)
- आईसीआरआईईआर की ओर से 27 मई, 2022 को 'भारतीय आर्थिक वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में नॉन– ऐल्कोहॉलिक पेय क्षेत्र के योगदान की रिपोर्ट का विमा. ोचन' कार्यक्रम में भाग लिया। (आभासी)
- यूएसएआईडी और आईएफपीआरआई की ओर से 24 मई, 2022 को 'सिंचाई निवेश नीतिः क्या पैमाना मायने रखता है?' विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।(आभासी)
- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) की ओर से 'निरंतर स्वस्थ आहार के लिए फल और सब्जियां (फ्रेश)' पर 25 मई, 2022 को आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।(आभासी)
- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) की ओर से '12 मई, 2022 को 2022 वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्टः जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियां' कार्यक्रम में भाग लिया।(वर्चुअल)
- एडीबी के सहयोग से 'आर्थिक दृष्टिकोणः प्रगति की संभावनाएं और क्षेत्रीय सहयोग' विषय पर 28 अप्रैल 2022 को आयोजित ईआरआईए कार्यक्रम में भाग लिया।(आभासी)
- 27 से 29 अप्रैल, 2022 के दौरान 'जी–20 इंडोनेशियाः विंडोज़ फॉर रिकवरिंग टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर' विषय पर आयोजित किए गए जी–20 इंडोनेशिया के साइड इवेंट सीएसआईएस ग्लोबल डायलॉग 2022 में भाग लिया।(आभासी)
- अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास, मुंबई द्वारा 26 अप्रैल 2022 को 'रीमैन्युफैक्चरिंगः द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।(आभासी)
- वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआ. रआई) इंडोनेशिया द्वारा 21 अप्रैल 2022 को थिंक–20 (टी20) द्वारा एक साइड इवेंट के दौरान 'रिकवर स्ट्रॉन्गर थ्रू द जी20ः सस्टेनेबल लैंडस्केप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीस इन एग्रीकल्चर' विषय पर आयोजित सेमिनार में भाग लिया। (आभासी)
- आईएफएडी द्वारा 11 अप्रैल 2022 को आयोजित 'ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणालियों में बदलाव : पोषण और पर्यावरण कैसे तालमेल बैठाते हैं?' शीर्षक से चर्चा में भाग लिया।(आभासी)

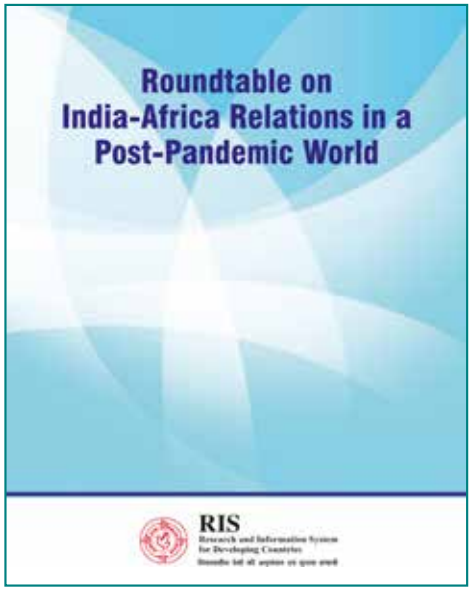

रिपोर्ट्स

- **महामारी के बाद की दुनिया में भारत-अफ्रीका संबंधों पर गोलमेज,** आरआईएस, नई दिल्ली, 2022
- **भारत और पड़ोसी देशों के बीच विकास सहयोगः संभावनाएं और चुनौतियां,** आरआईएस, नई दिल्ली, 2022

एफआईटीएम नीतिगत सारांश

#8 **हील बाय इंडिया, हील इन इंडियाः आयुर्वेद एंड योगा ऐज़ सॉफ्ट पावर टूल्स** प्रोफेसर टी. सी. जेम्स द्वारा

पत्रिकाएं

- **जी-20 डाइजेस्ट,** संस्करण : 1 संख्या 4
- **एशियन बायो टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू,** संस्करण : 24, संख्या 1, मार्च, 2022
- **ट्रेडिशनल मेडिसिन रिव्यू,** खंडः संस्करण : 1 संख्या 2 अप्रैल 2022

आरआईएस प्रकाशन में एआईसी

एआईसी कार्य पत्र

#10 **आसियान-इंडिया रिलेशन्सः द स्टॉक-टेकिंग ऑफ आउटकम्स फॉर 1992-2022,** संपा कुंडू द्वारा

मेकांग गंगा पॉलिसी ब्रीफ

संख्या 11, मार्च 2022

आरआईएस संकाय द्वारा बाहरी प्रकाशनों में योगदान

चतुर्वेदी, सचिन. 2022. सामाजिक क्षेत्रः समावेशी बुनियादी ढांचा, *योजना,* अप्रैल 2022

चतुर्वेदी, सचिन. 2022. स्ट्रेंगथनिंग बिम्सटेक पार्टनरशिप्स फॉर कलेक्टिव डेवलॅपमेंट. इन 25 ईयर्स ऑफ बिम्सटेक : टुअर्ड्स अ पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल, ढाका, बिम्सटेक सचिवालय, ढाका (पीपी.35–46)।

चतुर्वेदी, सचिन, टिम बुथे, पीटर बी पायोयो और कृष्णा रवि श्रीनिवास 2022. 'इंडिया एंड द फिलीपींस इन ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस' इन रीथिंकिंग पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस, जोस्ट पॉवेलिन, मार्टिनो मैगेटी, टिम बुथे, और आयलेट बर्मन द्वारा संपादित, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2022, (पीपी 349–378)।

लोकप्रिय लेख

चतुर्वेदी, एस एंड पोगे, थॉमस. 2022. इंडियाज़ स्टैंड ट्रिप्स वैक्सीन इनेक्विटी। *फाइनेंशियल एक्सप्रेस,* 08 जून, 2022

चतुर्वेदी, एस. 2022 . बांड्स ऑफ द बेः फुलफिलिंग द पोटेंशियल ऑफ बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी. *इंडियन एक्सप्रेस,* 09 अप्रैल, 2022

विकास की तलाश में दक्षिण एशिया का महत्व

प्रोफेसर दीपक नैय्यर
सह–अध्यक्ष,
एसएसीईपीएस

- त्वरित विकास ने ऐतिहासिक मानकों से दक्षिण एशिया में पूर्ण गरीबी में बहुत तेजी से कमी लाने में मदद की, लेकिन उतनी नहीं, जितनी हो सकती थी। इसका कारण प्रारंभिक आय वितरण का असमान होना और आय की असमानता में वृद्धि होना है।
- आर्थिक विकास से भी रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हुआ। दक्षिण एशिया दुनिया के 40 प्रतिशत से अधिक गरीबों का घर भी है। यहां के स्वास्थ्य और विकास से संबंधित सामाजिक संकेतक दुनिया में सबसे खराब हैं।
- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, उसकी विकास की जद्दोजहद में अत्यधिक महत्व रखता है। प्रारंभ में, दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग के तर्क और लाभ बड़े पैमाने पर व्यापार में माल से लाभ के रूप में निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी और लोगों से संबंधित आर्थिक लेन–देन भी होते हैं।
- हमारे देशों में संस्थाओं, व्यक्तियों, बुद्धिजीवियों, नागरिकों और नागरिक समाज को सार्क की भावना को बनाए रखना चाहिए। हालांकि, सरकारों के लिए एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया के विचार में भी जटिलताएं हैं।

क्षेत्रीय सहयोग की ओर अग्रसर

डॉ नागेश कुमार
निदेशक,
औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान,
नई दिल्ली

- पूरे क्षेत्र में गरीबी और भूख की चुनौतियां, बढ़ती और विकराल होती असमानता अभी तक बरकरार है और इनसे निपटने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी के उदय और वैश्वीकरण को इसमें योगदान देने वाले कुछ कारकों के रूप में इंगित किया गया है।
- दक्षिण एशियाई देशों के लिए सतत विकास लक्ष्य बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'कोई भी पीछे न छूटे'।
- मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय सहयोग अनिवार्य है। यदि दक्षिण एशिया सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने का इच्छुक है, तो वहां व्यापक क्षेत्रीय सहयोग होना चाहिए।
- साझा समस्याओं या साझा चुनौतियों के लिए साझा समाधानों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय या फ्रेट कॉरिडोर जैसे स्थायी परिवहन संपर्क बनाने की भी आवश्यकता है। संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने तथा इसे और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आधिकारिक संस्थाएं कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रही हैं। इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के बीच संपर्क और नागरिक समाज की भागीदारी की भी आवश्यकता है।

एकजुटता से सहयोग का आह्वान

डॉ देबप्रिया भट्टाचार्य
अध्यक्ष, सर्दन वॉयस नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स और विशिष्ट फेलो, सीपीडी, बांग्लादेश

- महामारी के दौरान महसूस किए गए दुख और अनुभव को भविष्य की पूंजी के समान माना जाना चाहिए। इससे हमें भविष्य के लिए बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए अपने सभी कदमों, अनुभव और संचित ज्ञान को निवेश करने में मदद मिलेगी। "हम एकजुट होकर उठ खड़े होंगे" हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए।
- अनेक समस्याएं ऐसी होती हैं, जिनका समाधान उसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर काम किए बिना नहीं निकाला जा सकता। जलवायु परिवर्तन, व्यापार, निवेश, वित्त, मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी, नवाचार, डेटा इत्यादि ऐसे ही लॉक्ड–इन सेक्टर/समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हल करने के निजी प्रयासों से उत्कृष्ट समाधान नहीं मिल सकते।
- अनिश्चितताओं से भरी दुनिया से एक सामूहिक क्षेत्रीय इकाई के रूप में निपटना सबसे बड़ा मुद्दा है। दुनिया में अनिश्चितता वस्तुओं की कीमतों में उतार–चढ़ाव, ऊर्जा क्षेत्र, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक मुद्दों में बदलाव, अन्य सॉफ्ट क्रॉस–बॉर्डर मुद्दों आदि के कारण हो सकती है। ये मुद्दे आपस में गुंथे हुए हैं और क्षेत्रीय हितधारकों के बीच सहयोग का आह्वान करते हैं।

दक्षिण एशिया में गहन एकीकरण को प्रोत्साहन

डॉ पोश राज पांडे
अध्यक्ष,
एसएडब्ल्यूटीईई,
नेपाल

- दक्षिण एशिया विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है। हालांकि दक्षिण एशिया में गहन एकीकरण को बढ़ावा देने के संबंध में आशावादी बने रहना चाहिए।
- आशावाद इस तथ्य से भी उपजता है कि आरआईएस, सीपीडी, आईपीएस, एसएडब्ल्यूटीईई, एसडीपीआई जैसे थिंक टैंक, अन्य शोध संस्थान और निजी क्षेत्र के हितधारक कृषि से लेकर नेट–जीरो कार्बन तक क्षेत्रीय सहयोग के लिए नए उत्प्रेरकों की पहचान के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
- अनुसंधान गतिविधियों और समर्थन गतिविधियों को जारी रखने की आवश्यकता है और क्षेत्रीय एकीकरण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राजनेताओं को अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर IV-B, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी मार्ग, नई दिल्ली–110 003, भारत। दूरभाष 91–11–24682177–80
फैक्स: 91–11–24682173–74, ईमेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: www.ris.org.in

हमें यहां फॉलो करें:
www.facebook.com/risindia @RIS_NewDelhi www.youtube.com/RISNewDelhi